सर्वोच्च प्राथमिकता

परिपत्र संख्याः डीजी– 19 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 27, 2018

विषयः स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग विभिन्न प्रकार के स्कूली वाहनों से स्कूल जाते हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी दिशा–निर्देश दिये गये हैं, किन्तु इसके बावजूद कई दुखद घटनायें स्कूली वाहनों में यात्रा करने वाले बच्चों के साथ घटित हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या डीजी–39/2012 दिनांक 17.08.12 के द्वारा आप सभी को विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। विभिन्न प्रकार के वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.12.1997** (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित निम्नलिखित प्राविधानों का सख्ती से अनुपालन कराया जाना आवश्यक है–

1. **प्रत्येक स्कूली वाहन के लिये सक्षम अधिकारी से समुचित परमिट यथा "Passenger Transport Vehicle Permit" प्राप्त होना चाहिये।**
2. **प्रत्येक स्कूली वाहन के आगे एवं पीछे On School Duty अवश्य अंकित होना चाहिये।**
3. **किसी भी स्कूली वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाये तथा किसी बच्चे को किसी अन्य की गोद में न बैठने दिया जाये।**
4. **प्रत्येक स्कूली वाहन में First Aid Box एवं पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।**
5. **आवश्यकतानुसार सीट बेल्ट उचित ढंग से लगाया जाये।**
6. **प्रत्येक स्कूली वाहन पर स्कूल का नाम, टेलीफोन नम्बर तथा चालक का नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर व मोबाइल नम्बर अवश्य दर्शाया जाये।**
7. **प्रत्येक स्कूली वाहन पर परिवहन विभाग/पुलिस विभाग के हेल्प लाइन नम्बर अवश्य अंकित किये जायें।**
8. **ऐसे प्रत्येक वाहन, जिसमे स्कूली बच्चे ले जाये जाते हो, के चालक को उस प्रकार के वाहनों को चलाने की न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिये तथा उसके विरूद्ध पूर्व में कोई यातायात सम्बन्धी अपराध का रिकार्ड नहीं होना चाहिये।**

9. **ऐसा चालक, जिसका 01 वर्ष में दो बार से अधिक लाल बत्ती के उल्लंघन, अनुचित पार्किंग, ओवरटेकिंग एवं किसी अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में चालान हुआ हो अथवा ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने और खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के सम्बन्ध में भा0द0वि0 की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए का एक बार भी अभियोग पंजीकृत हुआ हो तो ऐसे चालक को स्कूली वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

10. **जब भी स्कूली बच्चों को ले जाने के लिये किसी भाड़े के वाहन को प्रयोग में लाया जायेगा तो उक्त वाहन का स्वामी सम्बन्धित स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को वाहन के चालक एवं अन्य सुसंगत विवरण उपलब्ध करायेगा।**

11. **प्रत्येक ऐसे स्कूली वाहन में बच्चों के सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने तथा उनके वाहन में चढ़ने एवं वाहन से उतरने के दौरान एक परिचालक (Attendant) उपस्थित रहेगा।**

2– उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये–

1. प्रत्येक स्कूली वाहन में न्यूनतम 05 किग्रा0 के ए.बी.सी टाइप, जो आईएसआई मार्क से युक्त हो, के 02 Fire Extinguishers क्रमशः 01 चालक के केबिन में तथा दूसरा आपातकालीन निकास द्वार के पास होना चाहिये तथा ड्राइवर, कन्डक्टर, महिला अटेन्डेन्ट/गार्ड को Fire Extinguishers चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये।
2. चालक, कन्डक्टर व अटेन्डेन्ट का चरित्र सत्यापन अवश्य कराया जाना चाहिये।
3. स्कूली वाहन के चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज वाहन न चलाया जाये।
4. मोटर अधिनियम की धारा 19(1)एफ के साथ पठित केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 21 के भाग 25 के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ऐसा कार्य है, जिससे जनता के लिये न्यूसेन्स या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। अतः स्कूली वाहनों के तौर पर संचालित होने वाले वाहनों के चालकों द्वारा किसी भी दशा में वाहन चलाते समय न तो मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाये और न ही कान में ईयरफोन लगाकर वाहन का संचालन किया जाये।
5. यदि उपरोक्तानुसार चालकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा पुष्ट सूचना के आधार पर उनके लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
6. कामर्शियल/निजी वाहन अनधिकृत एल0पी0जी0 किट लगाकर संचालित न होने दिया जाये। इस सम्बन्ध में चैकिंग कराकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में समय-समय पर आकस्मिक रूप से चैकिंग कराकर नियमों से विचलन करने वाले वाहन चालकों/वाहन स्वामियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
8. परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के पत्र संख्या 72-इन्फ/2017-13इन्फ/2009-। दिनांक 19.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) में स्कूली वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिस पर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
9. उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निजी वाहन स्कूल वाहन के रूप में संचालित न हो रहे हों।

3- अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि स्कूली छात्रों की सुरक्षा हेतु स्कूली वाहनों के सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा **दिनांक 01.05.2018 से 15 दिवस का सघन अभियान सम्पूर्ण प्रदेश में चलाया जाये।** अभियान के द्वारा जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, विद्यालयों के प्रबन्धकों व सिविल सोसाइटी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाये। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाये। अभियान की कार्यवाही विधि सम्मत हो तथा जनसाधारण को कोई असुविधा न हो। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक इस अभियान को सफल बनाये जाने हेतु अपना मार्ग दर्शन जनपदों को प्रदान करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

27/4/18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Supreme Court of India

M.C.Mehta Etc vs Union Of India & Ors on 16 December, 1997

Bench: B.N. Kirpal, V.N. Khare

PETITIONER:
M.C.MEHTA ETC.

Vs.

RESPONDENT:
UNION OF INDIA & ORS.

DATE OF JUDGMENT: 16/12/1997

BENCH:
B.N. KIRPAL, V.N. KHARE

ACT:

HEADNOTE:

JUDGMENT:

THE 16TH DAY OF DECEMBER, 1997 Present:

Hon'ble the Chief Justice Hon'ble Mr. Justice B.N. Kirpal Hon'ble Mr. Justice V.N.Khare Ashok Desai, Attorney General, M.S.Usgeonkar, Additional Solicitor General, Hrish N.Salve, Sr.Adv., Mukul Mudgal, Ms.Indra Sawhney, Deepak Dewan, A.K.Sharma, S.Wasim A.Qadri, A.D.N.Rao, Ms. Niranjana Singh, (P.Parmeswarn) Adv. for (MOEF), Dutta, Hardeep Singh Anand, Shri Narain, Ssndeep Narain, (M.C.Mehta) (NP) In-person, Ms.Seema Midha, S.N.Sikka, D.S.Mehra, (Ms.Anil Katiyar) Adv. for (Min, of Petroleum), D.K.Garg, Sanjeev Pabby., R.K.Maheshwari, Ms.Manju Bharti, R.K.Kapoor, P.Verma, S.K.Srivastava, B.R.Kapur, Anis Ahmed Khan, Vijay Panjwani, (R.Sasiprabhu, Anees Ahmed, Aditi Singh) Advs. for (GAIL), Pradeep Misra.

Ms.Niti Dikshit, Sanjay parikh, Kailash Vasdev, Mahabir Singh, Ms. Sushma Suri, C.V.Subba Rao, Ashok Mathur, D.M.Nargolkar, Saharya, Ejaz Maqbool, R.P.Gupta, K.K.Gupta, L.K.Pandey, Upadhyay. S.R. Setia, Satish Aggarwal. Ranjit Kumar, Advs. with them for the appearing parties.

O R D E R The following order of the Court was delivered: (with W.P.(C) No.9300/02. W.P.(C) No. 939/96 and W.P.(C) No. 95/97/ After hearing the learned amicus curiae, the Additional Solicitor General and the counsel representing certain other interests, we issue the following further directions, namely.

(1) The figures in relation to issuance of commercial licences show that there is need to verify commercial licences. Which were issued during the period 1993-95. We. therefore, direct that all commercial licences issued during the period 1993-95 be re-verified by the Transport Department to weed out all such licences which have been issued without following the Rules.

(2) We are informed that a test has now been prescribed for issuance of new licence. We direct the Transport Department to prescribe a suitable refresher training course as a condition for the renewal of any licence to drive a heavy vehicle.

(3) The grantees of a permit cannot (without express prior permission). Under the provisions of the Motor Vehicles Act either transfer his permit or to allow some other person to operate a vehicle on this permit. Any such use of permits which really constitutes a trading in permits is a patent violation of the Motor Vehicles Act and the Rules and would render the permit liable to cancellation, apart from other legal consequences. We direct the authorities not to renew any permit which has been or is being used by any person other than the original grantee, without the express prior permission of the grantee.

(4) We direct the Civic Authorities to take necessary steps to remove immediately all encroachments- temporary or permanent - on roads and payments. Which affect the smooth flow of traffic or obstruct the way of pedestrians. Stay cattle and other similar obstructions would also have to be similarly dealt with.

(5) The need for safety of school children travelling in buses requires that such buses be fitted with doors that can be shut. We. therefore, direct that on or after 31st January, 1998. no bus shall be used by an educational institution unless it is fitted with doors which can be closed. No educational institutions shall, after the said date, use a bus if it has an open door.

(6) Similarly, it is essential that, in addition to a driver, there is another qualified person in the bus can attend to the children travelling in the bus. Rule 17 of the Motor Vehicles Rules. 1993 stipulates qualifications. duties and functions or a Conductor. It would be in the interest of safety to require the presence of a qualified conductor on board every bus that is being used by an educational institution. we are told that at present there is a paucity of trained conductors. We, therefore, direct that on or after 30th April, 1998. no bus used by or in the service of an educational institution shall be permitted to operate without a operate without a qualified conductor being present at all times. a (7) We are also informed that some schools have Voluntarily requested the parents of their wards to accompany buses so as to ensure that the drivers drive safely and the lives of the children are not out in jeopardy. we commend this action, and direct the education Department to ask all schools including Government and Municipal schools to evolve a similar arrangement as far as possible, so as to ensure that in each bus there is at least one parent present who would be able to oversee the conduct of the driver. This step would do a long way in ensuring that the directions given as well as other safety measures given as well as other safety measures prescribed are complied with in letter and spirit and that the driver drives carefully.

(8) One of the problems, which was been brought to our notice, is the overgrowing of buses. After hearing the views of the Transport Department as well as the Delhi Police (Traffic Wing), we feel it appropriate to direct, that no bus belongings to of in use of any educational institution, shall seat children in excess of 1.5 times its registered seating capacity. Similarly, other modes of public transport, such as TSRs, taxis and other vehicles used for transporting the students of an educational institution should not be permitted to carry children more than 1.5 times they registered seating capacity.

(9) One of the major pollutants identified in the various affidavits as well asa in the latest Status Report filed by the Government, is the TSR (two seater rickshaw using a two stroke engine). We are further informed that although the existing figures of registered TSRs as per the records, is approximately 83,000: the actual number in use is far lesser since some of these permits have bot been cancelled although the vehicles have been scrapped. It would be in the interest of the environment. to freeze the number of TSRs for the present at the level at which they are actually in use in the city. We. therefore direct that there would be no grant of fresh permits in respect of the TSR. save and except by way of replacement of an existing working TSR with a new one.

(10) We direct the police Commissioner to frame appropriate guidelines for regulating processions - religious. Political or otherwise - which tend to obstruct the flow of traffic. These guidelines should be in conformity with the rights of the users of the roads and the exercise of fundamental freedom of other citizens indicated by this Court in this judgment in Communist Party of India ((M) vs. Bharat Kumar and Others. JT 1997 (9) SC 101.

(11) The Union of India is directed to file within two weeks the Action Plan for appointment of private persons to enforce traffic safety laws and confer upon such people suitable powers under the Cr.P.C. as well as under the Motor Vehicles Act. The Union of India would also file its response to the repeated suggestion made by the Traffic Police as well as the Transport Department for augmenting the uniformed force in the city.

(12) There are certain modifications called for in our earlier order dated 20th November, 1997, which we direct as hereunder:

(1) In para A(a), add the following : "Requirement for installation of speed control devices would also not apply to vehicles operating on All India Tourist Permits issued by the Transport Department. NCT of Delhi".

(ii) In para A(f). the sentence commencing "no bus" and ending with "educational institution" shall stand substituted with the following "

"No bus belonging to or hired by an educational institution shall be driven by a driver who has -

(a) Less than fives years of experience of driving heavy vehicles;

(b) been challaned more than twice in a year in respect of offences of Jumping red fights. Improper or obstructive parking violating the stop line. violating the rule requiring driving within the bus lane. Violating restricting the overtaking. allowing unauthorised person to drive;

(c) been challaned/charged even once for the offence of over speeding, drunken driving and driving dangerously or for the offences under Sections 279,337,338 and 304-A of the Indian Penal Code. All such drivers would be dressed in a distinctive uniform and all such buses shall carry a suitable inscription to indicate that they are in the duty of an educational institution".

(iii) In para A(c). after the word "buses" add the words "heavy goods vehicles, medium goods vehicles, and A-wheel light goods vehicles plying during the permitted hours.

(iv) In para A(h). and the following : "Needless to add, this is in addition to the statutory power conferred under Section 115 of the Motor Vehicles Act under which the authorities can prohibited or restrict any class of vehicle(s) from being used, inter alia any particular route or during any period of time.

(14) The Transport as well as the Police Departments are directed to ensure that the contents of this order are duly publicised so that the people using roads are made aware of the restrictions imposed. They should also give publicity to the basic rules relating to safe driving, particularly those relating to user of bus lanes, changing of lane, overtaking and right of way on round about. We direct the Union of India to make available the necessary facilities in this regard, particularly in relation to the electronic media.